



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 27]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 20 जनवरी 2021-पौष 30, शक 1942

लोक सेवा प्रबंधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 जनवरी 2021

क्र. एफ-2-1-2021-इकसठ-1/लोसेप्र/पी.एस.जी.-बीस.- मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ-2-13-2012-61-1-लोसेप्र, दिनांक 10 अप्रैल 2013 में वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग से संबंधित सेवा क्रमांक 20.1, 20.2, 20.3, 20.6 एवं 20.7 को विलोपित (डी-नोटिफाई) किया जाता है :-

डी-नोटिफाई

उक्त अधिनियम की अधिसूचित सेवाओं को -

- (1) सेवा क्रमांक 20.1 - गुणवत्ता प्रमाणीकरण पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति को विलोपित (डी-नोटिफाई) किया जाता है.
- (2) सेवा क्रमांक 20.2 - परियोजना प्रतिवेदन व्यय प्रतिपूर्ति को विलोपित (डी-नोटिफाई) किया जाता है.
- (3) सेवा क्रमांक 20.3 - टर्मलोन पर ब्याज अनुदान स्वीकृति एवं वितरण (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विनिर्माण उद्यमों हेतु) को विलोपित (डी-नोटिफाई) किया जाता है.
- (4) सेवा क्रमांक 20.6 - माइक्रो, स्माल एण्ड मीडियम इन्टरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट, 2006 के तहत मेमोरैंडम जमा करने पर अभिस्वीकृति प्रदान करना, को विलोपित (डी-नोटिफाई) किया जाता है.
- (5) सेवा क्रमांक 20.7 - चिन्हित गैर प्रदूषणकारी उद्योगों के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करना को विलोपित (डी-नोटिफाई) किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रिपुदमन सिंह भदौरिया, उपसचिव.